भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1472

जिसका उत्तर 10 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

21 माघ, 1942 (शक)

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

1472. श्री विजय कुमार दुबे :
श्री रेबती त्रिपुरा :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सरकार ने कितनी सफलता प्राप्त की है और इस संबंध में सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने जनता के सशक्तिकरण में सरकार की डिजिटल पहल के द्वारा निभायी गई भूमिका के आकलन के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में ग्रामीण जनता के द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकियों को किस हद तक अपनाया है, के मापन के लिए कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं; और

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विगत तीन वर्षों में डिजिटल पहुंच और ई-गवर्नमेंट टूल्स के प्रयोग में राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी वृद्धि हुई है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री संजय धोत्रे)

(क): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार ने डिजिटल पहुंच, डिजिटल समावेशन, डिजिटल सशक्तिकरण, डिजिटल विभाजन को पाटने को सुनिश्चित करके भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम शुरू किया है। पूरे देश में सभी नागरिकों को ई-सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं/परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा की गई कुछ प्रमुख पहलों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

- **आधार** : आधार 12 अंकों की बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय आधारित पहचान प्रदान करता है जो विशिष्ट, आजीवन, ऑनलाइन और प्रामाणिक है। इसके अलावा, आधार को वैधानिक समर्थन देने के लिए मार्च 2016 को ' आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 अधिसूचित किया गया था। 128 करोड़ से अधिक निवासियों को नामांकन किया गया है।
- **कॉमन सर्विसेज सेंटर (सीएससी)** : कॉमन सर्विसेज सेंटर सेवा (गवर्नमेंट टू सिटिजन एंड बिजनेस टू सिटिजन) सेवा प्रदायगी हैं । अब तक, ग्राम पंचायत स्तरों पर 2.78 लाख सीएससी सहित 3.73 लाख कॉमन सर्विस सेंटर प्रचालनात्मक है।
- **डिजिटल विलेज**: एमईआईटीवाई ने अक्टूबर, 2018 में 'डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट' भी शुरू किया है। इस परियोजना के तहत 700 ग्राम पंचायतें (जीपीएस) / गांव जिसमें कम से कम प्रति जिले / राज्य संघ राज्य क्षेत्र एक ग्राम ग्राम पंचायत है, को इस परियोजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। डी जा रही डिजिटल सेवाओं में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा, वित्तीय सेवा, कौशल विकास, सरकार द्वारा नागरिक सेवाएं (जे2सी), बिजनेस टू सिटीजन (बी2सी) सेवाएं सहित सोलर पैनल संचालित स्ट्रीट लाइट हैं।
- **डिजिटल लॉकर**: डिजिटल लॉकर जारीकर्ताओं को डिजिटल रिपॉजिटरी में दस्तावेज अपलोड करने के लिए रिपॉजिटरी और गेटवे के संग्रह के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करता है। डिजीलॉकर के अब तक 5.5 करोड़ पंजीकृत उपयोगकर्ता को 426 करोड़ प्रामाणिक दस्तावेज जारी किए गए हैं। 872 जारीकर्ता और 148 अनुरोधकर्ता संगठन ऑन-बोर्ड किए गए हैं।
- **नेशनल रोलआउट ईजिला एमएमपी**: ईजिला एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है जिसका उद्देश्य जिला या उप जिला स्तर पर पहचान उच्च मात्रा नागरिक केंद्रित सेवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक वितरण करना है। 33 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में 705 जिलों में कुल 3,870 ई-जिला सेवाएं शुरू की गई हैं।
- **ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म**: ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफ़ॉर्म भारत सरकार की ओपन डेटा पहल का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। यह सरकार के कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाने का इरादा रखता है और विभिन्न दृष्टिकोणों को देने के लिए सरकारी डेटा के कई और नवीन उपयोगों के लिए रास्ते भी खोलता है। वर्तमान में, 175 मंत्रालयों / विभागों और राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 9,856 कैटलॉग के तहत 472,848 संसाधन प्रकाशित है।
- **ई अस्पताल/ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस):** ई अस्पताल के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली (ओआरएस) में नए रोगियों द्वारा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और पंजीकरण, प्रयोगशाला रिपोर्ट देखना, रक्त की उपलब्धता की स्थिति की जांच करना और भुगतान गेटवे (पे गव) के साथ एकीकरण शामिल है। अब तक, ओआरएस के माध्यम से 260 अस्पतालों में 36.56 लाख ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की गई हैं।
- **एनसीओजी- जीआईएस अनुप्रयोग:** नेशनल सेंटर ऑफ जियो- इंफॉर्मेटिक्स (एनसीओजीजी) परियोजना, विभागों के लिए साझाकरण, सहयोग, स्थान आधारित विश्लेषिकी और निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए विकसित एक जीआईएस मंच है। अब तक, विभिन्न डोमेन में 516 अनुप्रयोग चालू हैं।
- **न्यू-एज गवर्नेंस (उमंग) के लिए एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन**: उमंग को प्रमुख सरकारी सेवाओं को वितरित करने के लिए एकल मोबाइल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। 219 विभागों (केंद्रीय और राज्यों) से लगभग 20525 सेवाएं पहले से ही उमंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।
- **माई गव** : माई गव भारत में भागीदारी प्रशासन के लिए अपनी तरह का पहला नागरिक इनगेजमेंट मंच है। माईगव का उद्देश्य नागरिकों और सरकार के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना है, नागरिकों को सरकार के करीब लाना और सरकार को उन नागरिकों के करीब लाना है जो इस मंच के माध्यम से कार्य करते हैं। वर्तमान में, माईगव के साथ 1.51 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता पंजीकृत हैं , जो माईगव मंच पर होस्ट की गई विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं।
- **राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क:** एनकेएन का उद्देश्य संसाधनों और सहयोगात्मक अनुसंधान को साझा करने के लिए उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क के माध्यम से देश भर के सभी ज्ञान संस्थानों को आपस में जोड़ना है। इनमें सभी विश्वविद्यालयों, उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान से जुड़े लगभग 1500 संस्थान शामिल होंगे। एक उच्च गति डेटा संचार नेटवर्क स्थापित किया गया है ताकि उच्च शिक्षण संस्थानों और अनुसंधान को इंटरकनेक्ट किया जा सके। संस्थानों के लिए 1747 लिंक चालू और प्रचालनात्मक बनाये गए हैं। 516 एनकेएन लिंक पूरे भारत में एनआईसी जिला केंद्रों से जुड़े हैं। 4,450.10 करोड़ रु जारी किए गए हैं।

- **जीवन प्रमाण** : पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जीवन योजना जिसे जीवन प्रमाण के रूप में जाना जाता है , जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की परिकल्पना करती है। इस पहल के साथ, पेंशनभोगी को शारीरिक रूप से खुद को या खुद को वितरण एजेंसी या प्रमाणन प्राधिकरण के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है। 2014 के बाद से 4.46 करोड़ से अधिक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र संसाधित किए गए हैं।
- **प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा):** सरकार ने 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों (प्रति परिवार एक व्यक्ति) को शामिल करते हुए ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए " प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजीदिशा)" नामक एक नई योजना को मंजूरी दी है। अब तक, 4.22 करोड़ सेअधिक उम्मीदवारों को पीएमजीदिशा के तहत नामांकित किया गया है। 3.44 करोड़ उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है और इसमें से 2.51 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों को प्रमाणित किया गया है।
- **भारतनेट** : भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड क्रांति को गति देने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल है। यह परियोजना दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। भारतनेट का लक्ष्य देश की सभी 2, 50,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ना और सभी ग्राम पंचायतों (जीपी) को 100 एमबीपीएस कनेक्टिविटी प्रदान करना है। अब तक, कुल 1,51,431 ग्राम पंचायतों (ब्लॉक मुख्यालय सहित) को सर्विस रेडी किया गया है।

➢ **इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण**

- संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज (एम एसआईपी): दिनांक 5 फरवरी, 2021, को लगभग 81,085 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के साथ 294 आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं; लगभग 94,459 करोड़ रु के प्रस्तावित निवेश के साथ 17 आवेदन अनुमोदन के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा सिफारिश की गई है।
- इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी): इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी) योजना के तहत, 19 ग्रीनफील्ड ईएमसीएस और 3 सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसीएस) जिसका क्षेत्र 3,464 एकड़ है और 1,527 करोड़ रुपये की सरकारी अनुदान सहायता सहित 3,743 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत को देशभर के 15 राज्यों में मंजूर किए गए हैं। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्रों में लगी 227 कंपनियों ने 35,641 करोड़ रु के अनुमानित निवेश के साथ इन ईएमसी में अपनी विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थान बुक किया है। जिसमें से, 33 कंपनियों ने उत्पादन शुरू किया और लगभग 70 कंपनियों ने भी अपनी निर्माण गतिविधि शुरू कर दी है और कार्यान्वयन के विभिन्न चरण हैं।

डिजिटल इंडिया एक प्रमुख कार्यक्रम है जो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की कई परियोजनाओं को कवर करता है। प्रत्येक परियोजना की अपनी बजटीय आवश्यकता होती है और तदनुसार परियोजना-योजना का कार्यान्वयन मंत्रालय / विभागों द्वारा किया जाता है और बजट विवरण संबंधित मंत्रालयों / विभागों और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाए रखा जाता है। हालाँकि, पिछले चार वर्षों के दौरान डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एमईआईटीवाई द्वारा आवंटित और उपयोग किया गया बजट इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटित (करोड़ रुपये में)	वास्तविक व्यय (करोड़ रु में)
2017-18	1425.63	1451.59
2018-19	3352.81	3328.54
2019-20	3212.52	3191.09
2020-21	3044.82	1724.47 (31.01.2021 के स्थिति के अनुसार)

(ख): एमईआईटीवाई ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस योजना के लिए तीसरे पक्ष का मूल्यांकन किया है। अध्ययन की शुरुआत जनवरी 2020 में सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम्स (सीआईपीएस), हैदराबाद, तेलंगाना द्वारा की गई और अक्टूबर, 2020 में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रेरित, ई-गवर्नेंस विभिन्न सूचनाओं को एकीकृत करके, सूचना तक पहुंच प्रदान करके नागरिक सेवाओं को बदल रही है। सरकार और नागरिकों के बीच प्रणाली और सेवाएं, जिससे नागरिक के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक मूल्यों को सशक्त और बढ़ाया जा सके। ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के संबंध में अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- अध्ययन के नमूना लाभार्थियों के 88 (अट्ठासी) प्रतिशत ने यह संकेत दिया है कि किसी भी ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने की लागत मैनुअल सिस्टम की तुलना में काफी कम हो गई है। इसका मतलब है कि किए गए ट्रिप्स की संख्या, आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च प्रति ट्रिप, माध्यास्थों का उन्मूलन आदि से संबंधित लागत में कमी।
- अध्ययन के नमूना लाभार्थियों में से निन्यानबे प्रतिशत ने संकेत दिया कि ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने में आसानी से काफी सुधार हुआ है। यह सेवा वितरण चैनलों (मोबाइल, पोर्टल, कियोस्क आदि) की व्यापक रेंज और इन चैनलों पर सेवा की उपलब्धता के कुछ घंटों की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(ग) और (घ): इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और एनईआर राज्यों में डिजिटल तकनीकों को अपनाने की सीमा को मापने के लिए कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया है। हालांकि, ई- ताल मंच (https://etaal.gov.in/) पर ई-लेन-देन के आँकड़े भारत में डिजिटल प्रवेश में वृद्धि और ई-सरकार के उपकरणों के उपयोग का संकेत देते हैं। वर्ष 2020 के दौरान 3,949 सेवाओं के लिए 622 करोड़ से अधिक ई-लेनदेन दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और एनईआर में पिछले 3 वर्षों के दौरान ई-लेनदेन की संख्या इस प्रकार है।

राज्यों	ई-लेन-देन की संख्या (करोड़ में)		
	2018	2019	2020
उत्तर प्रदेश	34.68	39.91	38.39
अरुणाचल प्रदेश	0.35	0.41	0.40
असम	3.76	6.27	4.51
मणिपुर	0.23	0.27	0.26
मेघालय	0.39	0.30	0.27
मिजोरम	0.21	0.20	0.25
नागालैंड	0.23	0.26	0.29
सिक्किम	0.09	0.11	0.10
त्रिपुरा	0.36	0.60	0.49

****